



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2010/अग्रहायण 16, 1932

No. 305]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2010/AGRAHAYANA 16, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

विषय :—यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया तथा जापान से भारत में मेलामाइन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

फा. सं. 14/35/2010-डीजीएडी.—यतः मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., वडोदरा (जिसे एतद्पश्चात् आवेदक या याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया तथा जापान (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है जो एक स्वादरहित, गंधरहित और अविषाक्त पदार्थ है। मेलामाइन फॉर्मेलिडहाइड रेजिन का उपयोग लेमिनेट्स के लिए किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक कठोर होता है और यह खरोंच, धब्बों, पानी और ऊष्मा के प्रति रोधन क्षमता रखता है। कुछ इलेक्ट्रिकल अनुप्रयोगों में प्रयुक्त लेमिनेट्स में उच्च यांत्रिकीय दृढ़ता, उच्च ऊष्मा प्रतिरोधन क्षमता और उत्कृष्ट विद्युत प्रतिरोधन गुण होते हैं। एस्बेस्टॉस युक्त मेलामाइन रेजिन्स में अत्यधिक डायइलेक्ट्रिक सुदृढ़ता और उच्च प्रतिरोधन क्षमता होती है। सर्वोत्तम विमितीय स्थिरता के अतिरिक्त मेलामाइन फॉर्मेलिडहाइड मोल्डिंग पाउडर साफ तथा चमकीले रंग का होता है, आसानी से मोल्ड किया जा सकता है और उसकी सतह पर खरोंच नहीं आती है।

मेलामाइन की फॉर्मेलिडहाइड के साथ प्रतिक्रिया की जाती है और सौंदर्य प्रसाधन तथा उपयोगिता के अनेक उत्पादों के विनिर्माण हेतु उससे रेजिन्स अथवा मोल्डिंग पाउडर बनाया जाता है। मेलामाइन का प्रयोग मेलामाइन फॉर्मेलिडहाइड बनाने के लिए किया जाता है जिसका इस्तेमाल गौण उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।

संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष सं. 29336100 के तहत वर्गीकृत है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संदर्भ के प्रयोजनार्थ है और यह मौजूदा जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं होगा।

2. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में परस्पर तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों के रूप में संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

3. घरेलू उद्योग की स्थिति

वर्तमान याचिका मै0 गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0 (जीएसएफसी) द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उत्पादन में अवरोध के समय उन्होंने अपने छोटे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात किए थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता से इस सामग्री का आयात करने और इसकी आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। आवेदक ने निवेदन किया है कि सीमाशुल्क निकासी हेतु इन आयातों से संबंधित प्रवेश बीजक भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात उनके उत्पादन के 11.78% कुल आयातों के 7.44% और जाँच अवधि के दौरान भारत में खपत के 4.57% थे। प्राधिकारी ने इस मामले की जाँच की है और उनका अभिमत है कि याचिकाकर्ता जाहिर तौर पर व्यापारी नहीं है और पाटन का लाभ उठाने के लिए आयातों का सहारा नहीं ले रहा है। प्राधिकारी का विचार है कि जीएसएफसी ने आयातों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है और कम्पनी आयातक व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। कम्पनी का ध्यान उत्पादक बने रहने और स्वयं उत्पादन करने पर केन्द्रित है।

यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता भारत में मेलामाइन का एकमात्र उत्पाद है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जाँच के बाद प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि आवेदक नियम 2 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करता है।

4. शामिल देश

वर्तमान जाँच में शामिल देश यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया तथा जापान है।

5. सामान्य मूल्य

आवेदक ने यह सूचित करते हुए संबद्ध देशों के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्यों का परिकलन किया है कि वे संबद्ध देशों में घरेलू कीमतों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना जुटाने में असमर्थ रहे हैं और ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध नहीं है।

प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और संबद्ध देशों के लिए उचित लाभ सहित उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्यों के संबंध में पर्याप्त दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

6. निर्यात कीमत

संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण गौण स्रोतों से एकत्रित सौदे-वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और पत्तन व्यय आदि के लिए समायोजन किए गए हैं।

7. पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस आशय के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। इस सूचना के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि जाँच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन तथा खपत के अनुपात में संबद्ध देशों से आयातों में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में कमी, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट, निवेश पर आय और नकद लाभ में उल्लेखनीय कमी जैसे विभिन्न आर्थिक मानदंड प्रथम दृष्टया सामूहिक तथा संचयी रूप से यह संकेत करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करना

उपर्युक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के मतानुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। अतः प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क, जो लागू किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए एतद्वारा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

10. जांच अवधि (पीओआई)

आवेदक ने जाँच अवधि के रूप में अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 अवधि का प्रस्ताव किया था और याचिका में इस अवधि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई थी। आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त प्राधिकारी ने प्रस्तावित अवधि को बढ़ाना उचित समझा और वर्तमान जांच हेतु अप्रैल, 2009 से जून, 2010 (15 माह) की अवधि पर जांच अवधि के रूप में विचार किया है। तथापि क्षति की जांच अवधि 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जांच अवधि (पीओआई) होगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके अपने-अपने दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित विधि और पद्धति से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर संगत सूचना भेज सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
कमरा सं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु के ऐसे औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो पाटन क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संबंधित अपने अनुरोध नीचे दी गई निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

12. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें संबोधित पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

13. सूचना प्रस्तुत करना

नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार

की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना जुटाने से इंकार करता है, अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल रखी जाती है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2010

Subject :—Initiation of anti-dumping Investigation concerning imports of Melamine in India from European Union, Iran, Indonesia and Japan.

F. No. 14/35/2010-DGAD.—Whereas M/s. Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd., Vadodra (hereinafter also referred to as applicant or petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of melamine (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan (hereinafter also referred to as "subject countries") and requested for initiation of Anti-dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is Melamine, a tasteless, odorless and non-toxic substance. Melamine formaldehyde resin is used for laminates as it offers good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties. Asbestos filled Melamine resins possess very high dielectric strength and high resistance. Beside the best dimensional stability, Melamine Formaldehyde moulding powder gives clear and bright colors, easily moldable and offers resistance to surface scratching.

Melamine is reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products.

The subject goods is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act at sub-heading No. 2933 61 00. The customs classification is however is for reference purpose only and will have no binding on the scope of the present investigation.

2. LIKE ARTICLE

The applicant has claimed that there are no known differences in subject goods produced by the petitioner and exported from subject countries. Both products have comparable

4666GI/10-2

characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of essential product properties. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from subject countries.

3. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The present petition is filed by M/s Gujarat State Fertilizers and Chemical Ltd (GSFC). The petitioner has stated that they have made imports at the time of their production disruption to facilitate requirements of its small customers, who wished the petitioner to import the material and supply the same. It has been submitted by the applicant that bill of entry for these imports for customs clearance were not filed by them. Further, the imports made by the petitioner constituted approx 11.78 % of its production, 7.44% of total imports and 4.57% of consumption in India during the POI. The Authority has examined the matter and it holds that the Petitioner is not a trader per se and is not resorting to imports in order to take advantage of dumping. The Authority is of the view that the focus of GSFC has not turned to imports and the company is not behaving like an importer trader. The focus of the company continues to be a producer and do its own production.

It is noted that the Petitioner is the sole producer of Melamine in India. The Authority after examining the information on record determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

4. COUNTRY INVOLVED

The countries involved in the present investigation are European Union, Iran, Indonesia and Japan.

5. NORMAL VALUE

The applicant has constructed the normal values of subject goods in respect of subject countries stating that they are not able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in the subject countries and the same is also not available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed cost of production including selling, general and administrative overheads and reasonable profit for subject countries.

There is sufficient prima facie evidence with regard to normal values claimed by the petitioner.

6. EXPORT PRICE

Export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering transaction-wise import data collected from Secondary Sources. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, and port

expenses etc. in the exporting country to arrive at ex-factory export price. There is sufficient prima facie evidence with regard to export price claimed by the petitioner.

7. DUMPING MARGIN

Normal value and export price has been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries into the Indian market.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Analysis of the information shows that imports from subject countries have increased in the period of investigation in absolute term as also in relation to production and consumption in India. Various economic parameters like the loss in market share, significant decline in the profitability of the domestic industry, significant deterioration in return on investment and cash profit, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry have suffered material injury on account of dumped imports of subject goods from subject countries.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The applicant had proposed April-09 to March-10 as period of investigation and provided relevant information for this period in the petition. After analyzing the data, the Authority has found it appropriate to extend the proposed period and has considered April-09 to June-10 (15 months) as period of investigation for the present investigation. The injury investigation period will however be 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and POI.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject country, Governments through the Embassies, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 243, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110011.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

13. SUBMISSION OF INFORMATION

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority